

परियोजना का नाम :- रिवरभाण्डे गण्डाई मो० मार्ग लम्बाई - 12.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नाकोट (सैलोनी राजख ग्राम)
तहसील गण्डाईगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरभाण्डे गण्डाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.50 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.50 हे० सिविल सौयम भूमि X हे०, वन पंचायत भूमि X हे०) अर्थात् कुल 0.5 हे० वन भूमि का एजेन्सी निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सैलोनी द्वारा दिनांक 5-6-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सैलोनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि एजेन्सी निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव श्री ५. डि. क.
नाकोट

5-8-2017
ग्राम प्रधान नाकोट
गण्डाईगोली (पिथौरागढ़)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधान 5-5-2017
ग्राम सभा नाकोट
हो गंगोली हट (पिथौरागढ़)
ग्राम प्रधान

1.6

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- रिवरमाउंट गण्डि में मार्ग लम्बाई 12.10 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मैदोली
तहसील गण्डि जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाउंट गण्डि परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.40 हे० सिविल सौयम भूमि, X हे० वन पंचायत भूमि X हे०) अर्थात् कुल 0.4 हे० वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मैदोली द्वारा दिनांक 01/06/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मैदोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मैदोली

मुकेश जोगी
महामंत्री
भारतीय जनता पार्टी
ग्रामीण मन्त्र-मंडली, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

प्रधान
ग्राम पंचायत मैदोली
पिथौरागढ़ जिला
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधान
श्याम प्रकाश मातोली
विश्व-गंगोलीहाट
जयपुर जिला रागद
प्रधान

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- रिवरमाफे गणार्ड मोटर मार्ग लम्बाई - 12.00 कि.मी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बज्यूडा
तहसील गणार्डगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाफे गणार्ड परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.60 हे० सिविल सौयम भूमि X हे०, वन पंचायत भूमि X हे०) अर्थात् कुल 0.60 हे० वन भूमि का होना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बज्यूडा द्वारा दिनांक 01/06/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बज्यूडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ग्राम पंचायत बज्यूडा
ग्राम सचिव सुखदेव
दि० २०-०६-२०१४
वि० ख०-गंगोलीहाट (पिथौरा)

प्रमाणित
ग्राम पंचायत खडकी-बज्यूडा
वि० ख०-गंगोलीहाट
ग्राम प्रधान
जनपद-पिथौरागढ़

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 1-6-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खड़की

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्याम लाल	Shyam Lal
2	बन्नी लाल	Bahya
3	गवीन सिंह	Narayan
4	पुष्प लाल सिंह	Pustha
5	धन लाल	Dhan Lal
6	कुशाल सिंह	Kushal
7	पुष्प सिंह	Pustha
8	राजन सिंह	Rajan
9	रम लाल सिंह	Ram Lal Singh
10	मुषा लाल	Musha Lal
11	पुष्प लाल	Pustha Lal
12	जश लाल	Jash Lal


 प्रधान 1-6-2017
 ग्राम पंचायत खड़की-बज्यूड़ा
 विहरी-गंगोलीहाट
 जयप्रकाश नगर

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- रिवरमाफ्टे गण्डाई मो० मार्ग लम्बाई- 12.00 किमी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जमडलेख
तहसील गण्डाई गंगोली जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाफ्टे गण्डाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.20 हे० सिविल सोयम भूमि, 6075 हे० वन पंचायत भूमि — * — हे०) अर्थात् कुल 8075 हे० वन भूमि का पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जमडलेख द्वारा दिनांक 1.6.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जमडलेख के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो
ग्राम सचिव
क्षेत्र मातोली
वि०ख०-गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

महामंत्री
भारतीय जनता पार्टी
ग्रामीण मण्डल-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ (उ०प्र०)

जालिमा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत मातोली
वि०ख०-गंगोलीहाट
जनपद-पिथौरागढ़
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1

दिनांक 1-6-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जमडलेश्व

01-06-73
मुक्ति जोगी
महामंत्री
भारतीय जनता पार्टी
जगदीश मन्द-मंजोरीहट, पिबौरगढ़ (उत्तराखण्ड)

मानिदा देवी
प्रधान
श्याम मंचायत मातोळी
वि० ४० - मातोळी हाट
ज. मा. - सिंगोदागढ़
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- रिवरभाण्डे गण्डाई ओम्मार्ग लम्बाई - 12.00 किमी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भैसात
तहसील गण्डाई गंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरभाण्डे गण्डाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.9 - हे० सिविल सौयम भूमि, 0.9 हे० वन पंचायत भूमि X - हे०) अर्थात् कुल 0.9 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भैसात द्वारा दिनांक 01/06/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भैसात के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[Signature]
ग्राम वि० वि०
क्षेत्राध्यक्ष रविशंकर
वि० वि० - गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

[Signature]
ग्राम पंचायत खड़की-बज्यूडी
वि० वि० - गंगोलीहाट
जनपद पिथौरागढ़

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 1-6-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भैसात

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	तेजे सिंह	
2	राजेश सिंह	
3	भैरव सिंह	
4	गुरन सिंह	
5	आनंद सिंह	
6	धन सिंह	
7	आनंद लाल	
8	गोपाल - चन्द	
9	शेख लाल	
10	धन लाल	
11	गोपाल सिंह	
12	सर्व जीत सिंह	
13	शेख सिंह	

प्रधान 1-6-2017
ग्राम पंचायत खड़की-बनारस
वि० सं० 7 गंगोलाहट
जनप्रतिनिधि भौसागढ

परियोजना का नाम :- रिवरमाण्डे गण्डाई मोटर मार्ग लम्बाई-12 किमी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम अनौली
तहसील गण्डाई जंगली जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गण्डाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.67 हे० सिविल सौयम भूमि...X हे०, वन पंचायत भूमि X हे०) अर्थात् कुल 0.67 हे० वन भूमि का लोक निमाण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अनौली द्वारा दिनांक 30.5.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अनौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम ह० विकास अधिकारी
क्षेत्र ग्राम सचिव अनौली
वि० ख० गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)
6/6/17

30/5/2017
ह०
ग्राम प्रधान
क्षेत्र ग्राम पंचायत अनौली
वि० ख० गंगोलीहाट, विरवाहा

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 30.5.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अनौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री फकीर सिंह	श्री ड. ग. सिंह
2-	श्री मोहन सिंह	श्री ड. ग. सिंह
3-	श्री क-दा सिंह	श्री ड. ग. सिंह
4-	श्री लोपती सिंह	श्री ड. ग. सिंह
5-	श्री लोपती शर्मा	श्री ड. ग. सिंह
6-	श्री क-दा सिंह	श्री ड. ग. सिंह
7-	श्री सुपाल सिंह	श्री ड. ग. सिंह
8-	श्री शूर सिंह	श्री ड. ग. सिंह
9-	श्री नर-सिंह सिंह	श्री ड. ग. सिंह
10-	श्री नर-सिंह सिंह	श्री ड. ग. सिंह
11-	श्री हरि सिंह	श्री ड. ग. सिंह
12-	श्री हरि सिंह	श्री ड. ग. सिंह
13-	श्री नर-सिंह सिंह	श्री ड. ग. सिंह
14-	श्री सारंग सिंह	श्री ड. ग. सिंह
15-	श्री नर-सिंह सिंह	श्री ड. ग. सिंह

हस्ताक्षर
30/5/2017
हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान
वि० सं० ० मंगोलिया, विद्याराग

परियोजना का नाम :- खिरमाण्डे गाण्डे मोटर मार्ग लम्बाई-12 किमी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खडकी

तहसील गण्डे गोली जिला पिछौरा

उत्तराखण्ड में जनपद पिछौरा के अन्तर्गत खिरमाण्डे गाण्डे परियोजना के निर्माण हेतु (0.100 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.53 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.25 हे० वन पंचायत भूमि -X- हे०) अर्थात् कुल 6425 हे० वन भूमि का

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खडकी द्वारा दिनांक 01/06/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खडकी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10/10/20 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/40 दि० 20
ग्राम सचिव खडकी बज्जूड़ा
वि० ख०-गंगोलीहाट (पिछौरा)

प्रधान 1-6-2014
ग्राम पंचायत खडकी-बज्जूड़ा
वि० ख०-गंगोलीहाट
जनमस-पिछौरा गण्डे

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 1-6-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खडकी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हेमल सिंह	Heemal Singh
2	जगत सिंह	Jagat Singh
3	अरुण सिंह	Arun Singh
4	हयाद सिंह	Hyad Singh
5	शंकर सिंह	Shankar Singh
6	आनन्द सिंह	Anand Singh
7	धन राम	Dhan Ram
8	आनन्द राय	Anand Ray
9	Sanjay Singh	Sanjay Singh
10	संजय सिंह	Sanjay Singh
11	बालमो सिंह	Balram Singh
12	बालमो लाल सिंह	Balram Singh

प्रमाणित 1-6-2017
ग्राम पंचायत खडकी-बज्जुडा
हि.0.ख.0-गंगोलीहाट
ग्रामपंचायत विधायक

परियोजना का नाम :- खिरभाण्डे गण्डाई मोठ मार्ग लम्बाई-12.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नैनोली
तहसील गण्डाई गंगोली जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खिरभाण्डे गण्डाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.985 हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि X - हे०) अर्थात् कुल 0.985 हे० वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैनोली द्वारा दिनांक 31/05/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
वि०ख०-गंगोलीहाट(पिथौरागढ़)

ग्राम प्रधान
वि०ख०-गंगोलीहाट(पिथौरागढ़)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 31-5-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नैनीली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जोगा राम	
2-	विमान सिंह	विमान सिंह
3-	देव सिंह	देव सिंह
4-	राजन सिंह	राजन सिंह
5-	महाबल सिंह	महाबल सिंह
6-	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
7-	नर सिंह	नर सिंह
8-	पूत सिंह	पूत सिंह
9-	बलराम सिंह	बलराम सिंह
10-	कुल सिंह	कुल सिंह

31/5/2017
 प्रधान
 ग्राम पंचायत नैनीली
 वि० नं० ४०/गंगोलीहाट
 जन्म नं० मिर्जागढ़
 ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में
रिवरमाण्डे गण्डई मोटर मार्ग लम्बाई-12.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- धपना
तहसील गण्डई गंगोली जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गण्डई परियोजना के निर्माण हेतु (०.०० हे० आरक्षित वन भूमि, ०.६५० हे० सिविल सोयम भूमि × हे०, वन पंचायत भूमि × हे०) अर्थात् कुल ०.६५ हे० वन भूमि का नौक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत - धपना द्वारा दिनांक 4-6-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपर्युक्त के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि नौक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

20/06/17
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
भूत ग्राम सचिव
खण्ड गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

20/06/17
ग्राम पंचायत प्रभुकिटान
खंड ३० गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 4/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतधपना.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुष्पा सिंह	
2	हुन्द सिंह	
3	महेश सिंह	
4	पताई सिंह	
5	गोपाल सिंह	
6	महेश राम	
7	पद्माश्री चन्द	
8	जगदीश चन्द	
9	कृष्ण कुमार	
10	सोपान राम	
11	मोहन सिंह	
12	पूजा सिंह	

उमा देवी
प्रधान

ग्राम पंचायत - मकिटाण
पिन को 30 मीटर (विद्युतकर्म)

हो 7/11
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत - मकिटाण
पिन को 30 मीटर (विद्युतकर्म)

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में
रिवरमाण्डे गणार्ड मोटर मार्ग लम्बाई-12.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गुनाकिटाण
तहसील गणार्ड गंगोली जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गणार्ड परियोजना के निर्माण हेतु (०.०० हे० आरक्षित वन भूमि, ०.१३२५ हे० सिविल सोयम भूमि, ६११५ हे०, वन पंचायत भूमि ५ हे०) अर्थात् कुल १६३ हे० वन भूमि का लोकर निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गुनाकिटाण द्वारा दिनांक ५-६-१७ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपरोक्त के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोकर निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

24/06/17
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
भूत ग्राम सचिव
खण्ड गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

24/06/17
ग्राम पंचायत प्रमुखाकिटाण
खंड गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 5/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गुनाकिटाण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुष्पा सिंह	
2	हुन्द सिंह	
3	महेश सिंह	
4	पिता सिंह	
5	गोपाल सिंह	
6	महेश राम	
7	पद्मा श्री चन्द	
8	जगदीश चन्द	
9	कृष्ण कुमार	
10	गोपाल सिंह	
11	मोन सिंह	
12	पूज सिंह	
13	नवल सिंह	
14	कुमार सिंह	
15	मंगल सिंह	
16	शंकर देव	
17	गोकुल सिंह	

उमा देवी
प्रधान

ग्राम पंचायत गुनाकिटाण
पिन 220 300000 (बिधौवावा)

होम
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत गुनाकिटाण
पिन 220 300000 (बिधौवावा)

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में
रिवरमाण्डे गण्डई मोटर मार्ग लम्बाई 12.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गंगोलीहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गंगोलीहाट

निर्माण हेतु उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गण्डई मो० मार्ग
(०.०० हे० आरक्षित वन भूमि ६३६७५ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि १५१७५ हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ७७८५ हे० वन भूमि) का
लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गण्डई गंगोली) की दिनांक ३०/८/२०१७ को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री वैभव गुप्ता उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट अध्यक्ष
- 2- श्री शम्भू राम भट्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री दापक भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी गंगोलीहाट सदस्य / सचिव Offhalt
- 4- श्री शान्ती देवी बी०डी०सी० क्षेत्र गंगोलीहाट सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

रिवरमाण्डे गण्डई मोटर मार्ग

परियोजना हेतु ७७८५ हे० वन

भूमि

लोक निर्माण विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, जैशनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत
रिवरमाण्डे गण्डाई मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.785...
हे० वन भूमि P.W.D. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद-.....
उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद-.....
उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट

शान्ती देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत

Uthatt
सहायक प्रमाण कल्याण अधिकारी
गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

तहसीलदार
गण्डाई गंगोली

पिथौरागढ़ वन विभाग
पिथौरागढ़

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector- Pithoragarh

No---

Dated---21/9/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.785** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Berinag** (name of user agency) for **khirmandey Ganai Moter road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **seloni, matoli, Bajuda, Jamadlekh, Bhesat, Anoli, Khadaki, Nanoli, Dhapan, Gunakitan**, village (s) in **Gangolihat** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.785** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature




(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

No---

Dated---21/9/2017

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **7.785** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D Berinag (name of user agency) for **khirmandey Ganai Moter road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **seloni, matoli, Bajuda, Jamadlek, Bhesat, Anoli, Khadaki, Nanoli, Dhapana, Gunakitan**, village (s) in **Gangolihat** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. ~~Dr. Ranjeet Sinha~~ ^{C. Rameshwar} I.A.S deputy commissioner **Pithoragarh** on dated 2.9.17. at time 4.30 PM. at in which application claiming rights in area measuring 7.785 hect for the construction of **Khirmandey Ganai Moter road** to forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Gangolihat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place **Pithoragarh**

Dated: 2.9.17


बिना अधिकारी
Deputy Commissioner-Chairman

District Level Committee

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

जिलास्तरीय समिति-पिथौरागढ़

उप खण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील बेरीनाग) की दिनांक 2-9-17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी० रविशंकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

- 1-श्री सी० रविशंकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष।
- 2-श्री विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य।
- 3-श्री पी० बी० सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव।
- 4-श्रीमती राजेन्द्र बोरा जिला पंचायत क्षेत्र गण्डाई गंगोली सदस्य।

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि खिरमाण्डे गण्डाई मो० मार्ग परियोजना हेतु 7.785 हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी
अध्यक्ष

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

सदस्य जिला पंचायत
सदस्य

राजेन्द्र सिंह बोरा
सदस्य
जिला पंचायत गण्डाई विबोराव
जनपद पिथौरागढ़

(रमेश सिंह मण्डारी)

सदस्य
जिला पंचायत, गण्डाई (गंगोली, गढ़)
पिथौरागढ़